इस बार चुनाव में स्वराज मांगो:

60 साल में हमने हर पार्टी और नेता को आजमा कर देख लिया। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। साफ है कि चुनाव में सिर्फ पार्टियां और नेता बदल देने से कुछ नहीं होगा। इस बार पार्टियों से स्वराज मांगो।

लोगों को स्वराज देने के लिए नये कानून लाने होगे। उस पार्टी को वोट दो जो ऐसे कानून लाने का वादा करे।

स्वराज आंदोलन या लोकराज आंदोलन या स्वराज अभियान या लोकराज अभियान या स्वशासन जैसे अलग-अलग नामों से पुकारा जाने वाला यह आंदोलन स्वराज को वैधाानिक और संवैधाानिक रुप देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए लोगों को एक साथ ला रहा है।

स्वराज अभियान में शामिल होने के लिए हमसे सम्पर्क करें

अधिक जानकारी के लिए:

स्वराज अभियान,
ए-119, कौशाबी,
गाजियाबाद-201010, उ.प्र.
फोन: 09654658028
Email: contact@lokrajandolan.org

www.lokrajandolan.org

स्वराज क्यों?

हमें स्वराज चाहिये।
स्वराज होगा तो जनता विकास खुद कर लेगी।

सच्ची लोकशाही केन्द्र में बैठे हुए 20 आदमी नहीं चला सकते। वो तो नीचे से हर गांव के लोगों द्वारा चलायी जानी चाहिये। ताकि सत्ता के केन्द्र बिंदु जो इस समय दिल्ली, कलकत्ता या बंबई जैसे बड़े शहरों में है, मैं उसे भारत के 7 लाख गांव में बांटना चाहूंगा...

Bapu
M.K Gandhi

क्या भारत सच में लोकतंत्र है?

■ यदि सरकारी टीचर स्कूल में पढ़ाने न आये, तो आप क्या कर सकते हैं?

■ यदि सरकारी डॉक्टर मरीज का इलाज नं करे, तो आप क्या कर सकते हैं?

■ यदि राशन दुकानदार सरेआम आपके राशन की चोरी करे, तो आप क्या कर सकते हैं?

■ यदि पुलिस वाला हमारी शिकायतं पर कोई कार्रवाई न करे, तो आप क्या कर सकते हैं?

■ यदि सरकारी इंजीनियर ठेकेदार से रिश्वत खाकर घटिया सड़क पास कर दे जो चंद दिनों में टूट जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं?

■ आप क्या कर सकते हैं यदि सफाईकर्मी अपना काम नहीं करते और आपका इलाका बदबू मारता है?

ज्यादा से ज्यादा हम बड़े अफसरों को शिकायत करते हैं लेकिन हमारी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं होती। कुल मिलाकर, सरकारी स्कूलों में न आने वाले शिक्षकों या सफाई न करने वाले सफाईकर्मियों, राशन दुकानदार, सरकारी ठेकेदार, नेताओं, पुलिस वालों या अफसरो पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

और यही कारण है कि आजादी के 62 साल बाद भी देश में इतनी अशिक्षा और गरीबी है। लोग टीबी जैसी सामान्य बीमारी से मर रहे हैं। लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। सड़कें टूटी हुई हैं और शहर गंदगी का ढ़ेर बन गए हैं।

कहने को तो लोकतंत्र में हम मालिक हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें हमारी भूमिका, सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने तक ही सीमित है। और अगले 5 साल हम नेताओं और अफसरो के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं जो हमारी एक नहीं सुनते।

स्वराज:

स्वराज का मतलब है ऐसे ही स्थानीय नेताओं और कर्मचारियों पर आम सभा (शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला सभा और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा) के ज़रिए लोगों का सीधा नियंत्रण। स्वराज होगा तो आम सभा स्थानीय अधिकारियों को तलब कर सकेगी और जरुरत पड़ने पर उन्हें दंडित भी कर सकेगी।

आम सभा की बैठक हर महीने होगी। अपने क्षेत्र से जुड़े हर मुद्दे पर आम सभा जो निर्णय लेगी, उसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अधिकारियों और चुने गए प्रतिनिधियों की होगी।

यदि चुने गए प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं के ख़िलाफ काम करेंगे, तो उन्हें वापस बुलाने का अधिकार भी आम सभा के पास होगा।

आम सभा तय करेगी कि उनके क्षेत्र में सरकारी फंड कैसे खर्च होगा। लोग इस तरह पैसा खर्च कर पायेंगे कि उनके इलाके में कोई भूखा न रहे, सब के सर पर छत हो, कोई अशिक्षित न रहे और सब को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। ऐसा क्यों होता है कि हमारी ज़िंदगी से जुड़ी योजनाएं दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में बैठ कर चंद नेता और अफसर बनाते हैं जिन्हें हमारी समस्याओं की कोई समझ ही नहीं होती? क्या हमें अपनी योजनाएं खुद बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए?

इसलिए आम सभा के माध्यम से अपने क्षेत्र के उन सभी मामलों का सीधा प्रबंधन, जो ग्राम सभा या मोहल्ला सभा के स्तर पर संभव है, लोग खुद करेंगे। केवल ऐसे ही मामले सरकार के उच्च स्तर पर जायेंगे जिनका प्रबंधन ग्राम सभा या मोहल्ला सभा के स्तर पर संभव नहीं है।

यदि किसी राज्य की ग्राम सभायें और मोहल्ला सभायें बहुमत से किसी मुद्दे पर मांग करती हैं तो उस राज्य सरकार को विधान सभा में उस मुद्दे पर कानून बनाना होगा।

यही सच्चा लोकतंत्र होगा
जो सीधे जनता के द्वारा चलाया जायेगा

यही स्वराज है, यही स्वशासन है, यही लोक राज है

प्राचीन भारत और अन्य देशों में स्वराज:

बुद्ध के जमाने से ले कर 1820 तक ऐसा ही होता था। लोगों की आम सभाये ही गांव को चलाती थीं। जितने विदेशी हमलावर आये, उन्होंने केवल केंद्रीय शासन पर ही कब्जा किया। गांवों को उनकी ग्राम सभायें ही चलाती रही। लेकिन 1820 के बाद अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को भंग कर कलेक्टर राज की स्थापना की जिसमें लोगों के अधिकारों को छीन कर उन्हें अंग्रेज नौकरशाहों के हाथों में दे दिया गया। दुर्भाग्यवश, आज़ादी के बाद हमने इसी व्ययस्था को कायम रखा। लोगों के छिने हुए अधिकार उन्हें वापस नहीं किए गए।

आज भी बहुत से देशों में जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्राजील इत्यादी देशों में लोगों की आम सभायें ही स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेती हैं।